evening—and there is no restriction of holding jewellery. In any case, this Act has been followed more in breach than in observance. So, this Act being repealed is welcome. The other measures, complementary measures, should be announced soon. Otherwise, today in the public the general impression is what Prof. Thakur has just now said, that by repealing this Act the prices will go down. But, actually, the prices will flare up after the Bill is passed and there is no restriction on holding gold. So there is the danger that prices will flare up.

The Deputy Finance Minister said that gold is not an essential commodity and so he tried to say that Government is not so much worried about the price of gold. But I submit that gold prices have a bearing on a lot of other things, like foreign exhange, black-market in foreign currency, *hawala* rates, etc., etc. So, I feel that the Finance Minister should seriously look into this matter at his level only because, I can assure him that a lot of economists and bureaucrats are going to say "No". He will have to take saner counsel from Members across the floor like Mr. Salve, come to some firm conclusions and take some very bold and dynamic decisions.

Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): Is it the consensus of the House that we continue the discussion and conclude it in half an hour and then take up the Half-an-Hour discussion at 6.30 because the Finance Minister...

6.00 P.M.

SOME HON. MEMBERS: No, tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): We will have to consider the Half-an-Hour discussion also. After the Half-an-Hour discussion we can again continue this discussion.

SOME HON. MEMBERS: No, Sir. We can continue the discussion tomorrow.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: I can make a beginning today, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): Now we will have the Half-an-Hour discussion. Further discussion on the Bill will continue tomorrow. Shri Virendra Verma.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

On points arising out of the Answer given in the Rajya Sabha on the 17th May, 1990 to Starred Question 223 Re. setting up Benches of High Courts

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, 1953 ई० से जिसको 37 वर्ष हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि पश्चिम प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की खण्ड पीठ स्थापित किये जाने के लिये निरंतर प्रयास कर रहे हैं। विधान सभा, विधान परिषद् में यह प्रश्न निरंतर उठता रहा और प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के सौभाग्य से वहां की सरकारों के प्रायः सभी मुख्य मंत्रियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की खण्ड पीठ को मेरठ में स्थापित करने के औचित्य को स्वीकार किया था। अब से 35 वर्ष पूर्व स्वर्गीय डा० सम्पूर्णानंद जी ने पहली बार और उसके पश्चात जितने भी प्रदेश के मुख्य मंत्री हुये प्रायः सभी ने लगातार मेरठ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की खण्ड पीठ स्थापित किये जाने की संस्तुतियां यहां पर सर्व-सम्मति से भेजी हैं। सन् 1976 ई० के फरवरी-मार्च महीने में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी मेरठ के भैंसाली ग्राऊंड की विशाल जनसभा में अपार जन समूह के सामने घोषणा करती है कि आपकी मांग सही है और मेरठ में खण्ड पीठ स्थापित की जायेगी। जिस समय भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव थे वह भी मेरठ बार एसोशियेशन के वार्षिक सम्मेलन में पहुंचे और उन्होंने भी मेरठ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बैंच के स्थापित किये जाने के औचित्य को स्वीकार किया और वहां घोषणा की कि हम जरूर मेरठ में हाई कोर्ट की बैंच स्थापित करायेंगे। इस औचित्य को स्वीकार करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश में विभिन्न प्रदेशों से भी खण्ड पीठ की मांगें उठती रहती थीं, उस आधार पर जसवंत सिंह आयोग का गठन किया। 30 अप्रैल, 1985 ई० में जसवंत सिंह आयोग ने अपनी संस्तुति भी

दी जिसको पूरे पांच वर्ष हो जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जो आज देश के प्रधान मंत्री हैं और जब वह मुख्य मंत्री थे उन्होंने भी मेरठ में खंड पीठ स्थापित किये जाने की संस्तुति केन्द्र को भेजी थी। केन्द्र भी सोता रहा। पांच वर्ष तक वह जसवंत आयोग भी रद्दी की टोकरी में पड़ा रहा। प्रधान मंत्री क्या निर्णय लेंगे वह तो वह जानते हैं लेकिन वचनबद्ध वह भी हैं। उन्होंने घोषणा की थी। नैतिक जिम्मेदारी उन पर भी है।

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): वचन दिया है तो पूरा भी करेंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा: पहले भी बहुत ने वचन दे रखे हैं। मैं यह कह रहा था कि अब वह क्या करते हैं, अपने वचन का कितना पालन करते हैं यह उनकी परीक्षा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट्स आंदोलन करते हैं। वहां के जजेज भी विरोध कर रहे हैं। मैं किसी भी चीफ जस्टिस से पूछता हूं कि क्या चीफ जस्टिस के लिए हाई कोर्ट स्थापित किये जाते हैं? हाई कोर्ट स्थापित किये जाते हैं जनता के लिए। जनता के ही मुकदमात होते हैं। उनके केसेज निपटाने के लिए ही हाई कोर्ट स्थापित किये जाते हैं। हाई कोर्ट्स न एडवोकेट्स के लिए होते हैं और न चीफ जस्टिस के लिए।

हमारे प्रदेश की जनसंख्या 14 करोड़ है। दुनिया का सातवां देश है आबादी की दृष्टि से। यहां न्याय मंत्री जी भी बैठे हैं। उनको पता है कि जम्मू और कश्मीर की आबादी 59 लाख है। पंजाब और हरियाणा की आबादी 3 करोड़ के करीब है। मध्य प्रदेश की आबादी साढ़े 5 करोड़ के करीब है। महाराष्ट्र की आबादी 6 करोड़ की है। अगर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों को जोड़ लिया जाए तो आबादी 11 करोड़ बैठती है जो उत्तर प्रदेश के बराबर बैठती है। दोनों में सात हाई कोर्ट के बैंच हैं। मध्य प्रदेश में तीन, महाराष्ट्र में चार, उत्तर प्रदेश में सवा—एक हाई कोर्ट में और एक बैंच लखनऊ में। केवल 12 जिले हैं लखनऊ में वहां एक बैंच है और कुल 63 जिले हैं उत्तर प्रदेश में जिसमें 51 जिलों की इलाहाबाद में है। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट को उठाना नहीं चाहते। देश के दो राष्ट्रपतियों ने घोषणा की है कि जनता को सुलभ, सस्ता और शीघ्र न्याय दिलाने की सरकार घोषणा करती है। राष्ट्रपति की यह घोषणा सरकार के निश्चय पर होती है। प्रधान मंत्री की चर्चा मैंने आपके सामने की। हमें तकलीफ है क्योंकि 800-900 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है न्याय प्राप्त करने के लिए। आपने कहा था कि डोर स्टेप पर न्याय देंगे। क्या डोर स्टेप 900 किलोमीटर पर होता है? आपके माध्यम से विनम्र निवेदन है कि इस देश की 76 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है जो ज्यादातर गरीब है और उन्हीं के ज्यादा मुकदमें होते हैं। और उन्हीं को मुकदमों पर न्याय प्राप्त करने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता है। न तो सस्ता न्याय मिला, न सुलभ न्याय मिला और न ही डोर स्टेप पर मिला। इसलिए हमारी मांग निरन्तर इतने दिनों से चल रही है। 1982 से 1989 तक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के सभी एडवोकेट लगातार हड़ताल कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं और कोर्ट में भी नहीं जाते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जनता के हित में, गरीबों के हित में, शीघ्र न्याय के हित में, सस्ते न्याय के हित में, सरकार को यह कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो निर्णय और निश्चय हुआ है उसको लागू करे। जहां तक यह कहते हैं कि जसवंत सिंह आयोग ने आगरा में बैंच स्थापित करने का निर्णय दिया है। आगरा पश्चिमी प्रदेश में एक तरफ पड़ता है। उत्तर प्रदेश की आबादी 14 करोड़ है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर आप आगरा में बनाना चाहें तो आगरा में बनायें, लेकिन मेरठ में जहां नम्बर आफ केसेज सबसे ज्यादा हैं, माननीय न्याय मंत्री जी ध्यान से सुनें, नम्बर आफ केसेज के आधार पर, जनता की सुविधा पर, जिनके लिए हाई कोर्ट बनता है उनके लिए आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की बैंच मेरठ में स्थापित करने का शीघ्र निर्णय लेकर जनता को न्याय दिलायें और जो वायदे किये हैं उन वायदों की पूर्ति करें। यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): श्री सुरेन्द्र सिंह—अनुपस्थित। श्री सुरेश पचौरी।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): मान्यवर, आदरणीय वर्मा जी ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है हाई कोर्ट बैंच स्थापित करने को लेकर। मध्य प्रदेश देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और पिछले दिनों 10 मार्च, 1986 को इसी राज्य सभा में बताया गया कि मध्य प्रदेश में दो स्थानों के लिए हाई कोर्ट बैंच की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसंशा की है, एक भोपाल में और दूसरे रायपुर में। भारत में जितने भी राज्य हैं, प्रायः सभी की राजधानियों में हाई कोर्ट की बैंचेज हैं। अपवादस्वरूप एक उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है जहां भोपाल की तरह हाई कोर्ट बैंच नहीं है। लेकिन भुवनेश्वर के बिलकुल निकट कटक में हाई कोर्ट बैंच है। उसूलन देखा जाय तो प्रदेशों की सभी राजधानियों में हाई कोर्ट की बैंचों को स्थापित किया जाना

[श्री सुरेश पचौरी]

अत्यन्त आवश्यक है। इसको सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि ज्यादातर शासकीय प्रकरण रहते हैं और शासकीय कर्मचारियों को इन प्रकरणों के निपटारे के लिए यदि दुर्भाग्यवश हाई कोर्ट की बैंच राजधानी में न हो तो अन्यत्र जाना होता है। यही स्थिति का सामना भोपाल के लोगों को भी करना पड़ रहा है। शासकीय प्रकरणों के निपटारे के लिए भोपाल के वासियों को, शासकीय कर्मचारियों को, अत्यन्त दूरस्थ स्थान जबलपुर जाना पड़ता है जिससे अनावश्यक खर्च शासन पर पड़ता है। अनावश्यक खर्च में कमी हो जाएगी और दूसरे राजधानी की गरिमा भी बनी रहे, इसे दृष्टिगत रखते हुए मेरा सरकार से आग्रह है कि भोपाल में हाई कोर्ट की बैंच स्थापित किया जाना एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से बहुत आवश्यक है। ठीक इसी तरीके से जोगराफिकल दृष्टि से रायपुर में भी भोपाल के बाद दूसरी हाई कोर्ट बैंच स्थापित किया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि छत्तीसगढ़ अंचल में एक भी हाई कोर्ट बैंच नहीं है। इसकी सिफारिश जसवंत सिंह कमीशन ने भी की है। मान्यवर, खुद हाई कोर्ट के जज जस्टिस गुलाब गुप्ता ने यह स्वीकारा है कि लगभग 50 हजार पेंडिंग केसेज 20 जून, 1990 तक लंबित पड़े थे। उन्होंने 20 जून को एक प्रेस कांफ्रेंस में यह बातें स्वीकारी है। इतनी अधिक मात्रा में मामले लंबित हैं, इसलिये उनके शीघ्र निपटारे की दृष्टि से यह जरूरी हो गया है कि अन्य स्थानों पर भी, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल को दृष्टिगत रखते हुए, हाई कोर्ट की बैंच स्थापित की जाये। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आवश्यक रूप से हाई कोर्ट की बैंच स्थापित किया जाना भोपाल में आवश्यक है, ऐसा मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान, केवल चार मिनट बोलने की कृपा करें।

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान (आंध्र प्रदेश): जनाब वाइस चेयरमैन साहब, मैं वर्मा जी का बड़ा मशकूर हूं जो उन्होंने हाई कोर्ट की बेचेंज के ताल्लुक से यहां मसला उठाया है और हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिये। आजादी के बाद से हमने देखा कि जूडीशियरी का जो विंग है, उस विंग में जो सहूलियतें पहुंचनी चाहिये थीं, वे सहूलियतें नहीं पहुंचाई गई हैं। जिस तरह से हमारी जूडीशियरी को तरक्की करनी चाहिये थी, उस तरह की बात नहीं हुई। तकरीबन हमारा जो जूडीशियरी का सिस्टम है वह वैसे ही है जैसा कि आजादी के पहले था। खासतौर पर स्टेट्स के रीआर्गनाइजेशन के बाद से यह जरूरी हो गया है। हिन्दुस्तान की कई स्टेट ऐसी हैं जिनमें हाई कोर्ट की बेचेंज बेहद जरूरी हैं। हाई कोर्ट की जहां बेंच कायम की जाती है उसके लिये सबसे पहले हमें यह देखना जरूरी है कि वह जो स्टेट है उस स्टेट का रकबा क्या है, उसका कितना बड़ा एरिया है। फिर, जहां पर हाई कोर्ट की लोकेशन है वह लोकेशन क्या सेंट्रली लोकेटेड प्लेस में है और उसके आसपास के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वहां के क्लाइंट वहां पर आसानी से जा सकते हैं और अपने मुकदमात वगैरह दाखिल कर सकते हैं। ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। फिर, खासतौर पर इंसाफ को हमें सस्ता करना चाहिए। लेकिन हम यह देखते हैं कि इंसाफ दिन-ब-दिन मंहगा होता चला जा रहा है जिससे यह मुमकिन नहीं है कि क्लाइंट इंसाफ हासिल कर सके, एक चीज। दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट में मुकदमात की फेहरस्त इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी बढ़ गई है कि मुकदमात का फैसला पाने के लिये कई साल दरकार होते हैं और जिस मकसद के लिये हाई कोर्ट में मुकदमात दायर किया जाता है उसका मकसद ही खत्म हो जाता है। दूसरा, जैसा कि इंगलिश में कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वह बात हो गई है। इसके लिये यह जरूरी है कि जो बड़ी-बड़ी स्टेट्स हैं वहां पर हाई कोर्ट की बेंच कायम की जाय। मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए यह कहना चाहता हूं कि हमारे आंध्र प्रदेश में उस वक्त सिर्फ एक ही हाई कोर्ट है और वह इस वक्त हैदराबाद में है। मेरा मताबला है कि गुंटूर में हाई कोर्ट की बेंच कायम की जाय। इसके ताल्लुक से बहुत दिनों से यह मताबला किया जा रहा है कि गुंटूर में हाई कोर्ट की बेंच कायम की जाय ताकि जितने भी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं, कृष्णा है, गुंटूर है, ईस्ट गोदावरी है, वेस्ट गोदावरी है, विशाखापटनम है, श्रीकाकुलम है, निल्लोर है, इनके क्लाइंट गुंटूर जाकर, जो उनके करीब है, इंसाफ हासिल कर सकें। लिहाजा मैं हुकूमत से पुरजोर मताबला करूंगा कि वह गुंटूर में हाई कोर्ट की बेंच कायम करने के नज़र से हमदर्दाना गौर करे और जल्दी से जल्दी गुंटूर में हाई कोर्ट की बेंच कायम करे।

شری محمد خلیل الرحمان - (آندھرا پردیش):
جناب وائس چیرمین صاحب۔
میں ورماجی کا بڑا مشکور ہوں

[Transliteration in Arabic Script.]

جتنے ڈسٹرکٹ ہیں وہاں کے
کلائنٹ وہاں پر آسانی سے جا
سکتے ہیں۔ اور اپنے مقدمات
وغیرہ داخل کر سکتے ہیں۔
یہ چیزیں دیکھنا بہت ضروری
ہے۔ پھر خاص طور پر انصاف
کو ہمیں سستا کرنا چاہئے۔
لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انصاف
دن بہ دن مہنگا ہوتا جا رہا ہے
جس سے یہ ممکن نہیں ہے کہ
کلائنٹ انصاف حاصل کر سکے
ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے
کہ ہائی کورٹ میں مقدمات
کی فہرست اتنی زیادہ ہو گئی
ہے۔ اتنی بڑھ گئی ہے کہ
مقدمات کا فیصلہ پانے کیلئے
کئی سال درکار ہوتی ہیں اور
جس مقصد کیلئے ہائی کورٹ
میں مقدمہ دائر کیا جاتا ہے
اسکا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے
دوسرا جیسا کہ انگلش میں
کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از
جسٹس ڈینائڈ۔ وہ بات ہو
گئی ہے۔ اسکے لئے ضروری ہے کہ

جو انہوں نے ہائی کورٹ کی
بینچیز کے تعلق سے یہاں مسئلہ
اٹھایا ہے اور حکومت کو اس پر
غور کرنا چاہئے۔ آزادی کے بعد
سے ہم نے دیکھا کہ جیوڈیشری
کا جو ونگ ہے۔ اس ونگ میں
جو سہولیتیں پہونچنی چاہئے
تھیں اس طرح کی بات نہیں
ہوئی۔ تقریباً ہمارا جو جیوڈیشری
کا سسٹم ہے وہ ویسے ہی ہے جیسا
کہ آزادی کے پہلے تھا۔ خاص طور
سے اسٹیٹس کے ری آرگنائزیشن
کے بعد سے یہ ضروری ہو گیا ہے۔
ہندوستان کی کئی اسٹیٹ ایسی
ہیں جن میں ہائی کورٹ کی بینچیز
بیحد ضروری ہیں۔ ہائی کورٹ کی
بینچ جہاں قائم کی جاتی ہے۔
اسکے لئے سب سے پہلے ہمیں یہ
دیکھنا ضروری ہے کہ وہ جو اسٹیٹ
ہے اس اسٹیٹ کا رقبہ کیا ہے
اسکا کتنا بڑا ایریا ہے۔ پھر جہاں
پر ہائی کورٹ کی لوکیشن ہے وہ
لوکیشن کیا سینٹرلی لوکیٹڈ پلیس
ہے۔ اور اس کے آس پاس کے

جلدی گنٹور میں ہائی کورٹ کی بینچ قائم کرنے

SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the half-an-hour discussion. I am also thankful to my hon. friend, Mr. Virendra Verma who has initiated this half-an-hour discussion. Before this question, another question was raised by the hon. Member, Mr. Gopalsamy and myself on the 11th May, 1990.

The right to speedy trial is one of the dimensions of right to life and liberty guaranteed by Article 21 of the Constitution. Unnecessary prolongation of trial for more than eight, nine or ten years without any fault of the affected person is a violation of the fundamental right. This is an observation of no less a person than a High Court Judge. I am also one of the victims of this malady. My appeal has been pending in the Madras High Court for more than 15 years. The arrears of cases not only in the Madras High Court but also in the other High Courts and even in the Supreme Court are soaring to lakhs. So far as I understand, there are two reasons for this. One is due to a number of vacancies in the High Courts and number two is, due to lack of proximity to the common public. Take, for example, the Madras High Court. It is at present situated at such a place that it is not easily accessible to the poor litigants from the southern districts of Tamil Nadu. Madras is 719 kms. from Kanyakumari district; 649 kms. from Nellai Kattabomman district, 492 kms from Madurai and about 500 kms from my own district, that is Pasumpon Thevar and Ramanathapuram. This means the poor men and women are left beyond the reach of justice. They have been forced to spend their time, money and energy beyond their capacity.

جو بڑی بڑی اسٹیٹس ہیں وہاں پر ہائی کورٹ کی بینچ قائم کی جائے۔ میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آندھرا پردیش میں اس وقت صرف ایک ہی ہائی کورٹ ہے وہ اس وقت حیدر آباد میں ہے۔ میرا مطالبہ ہے کہ گنٹور میں کوئی کورٹ کی بینچ قائم کی جائے اسکے تعلق سے بہت دنوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ گنٹور میں ہائی کورٹ کی بینچ قائم کی جائے تاکہ جتنے بھی کوسٹل ڈسٹرکٹ ہیں۔ کرشنا ہے۔ گنٹور ہے۔ ایسٹ گوداوری ہے۔ ویسٹ گوداوری ہے۔ وشاکھا پٹنم ہے۔ شری کاکولم ہے۔ نلور ہے۔ انکے کلائنٹ گنٹور جا کر جو انکے قریب ہے۔ انصاف حاصل کر سکیں۔ لہذا میں حکومت سے پرزور مطالبہ کرونگا کہ وہ گنٹور میں ہائی کورٹ کی بینچ قائم کرنے کی نظر سے ہمدردانہ غور کرے اور جلدی سے

Even after forty years of independence, the common man who lives in the far-flung and remote area is put in the same tragic position at which he was left during the British rule. Whereas the pendency of the main cases in the year 1979 was of the order of 34,497, it rose to 58,864 at the end of 1983. Likewise, miscellaneous cases have also been mounting up. As against 24,133 cases of this category which were pending at the close of the year 1979, their number shot up to 44,102 at the close of 1983. Thus the total number of both categories of cases at the close of the year 1983 rose to 1,02,966.

So far as the southern districts are concerned, the total number of main and miscellaneous cases pending with the High Court of Madras were 18,976 up to the year 1983. By this time, this figure could have further gone up. In view of this, there has been a persistent demand for setting up of a High Court Bench at Madurai. The general public, traders, businessmen, students, several voluntary organisations, almost all political parties, the Bar and the Advocates associations of Madurai as well as that of the Tamil Nadu State have been continuously demanding of the High Court, the Supreme Court and the Central Government for early setting up of a High Court Bench at Madurai. This demand for a Bench of the High Court is a long standing one dating back to the year 1968 when the Chambers of Commerce and Industry of Madurai and Ramnad presented a memorandum to the then Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, urging the dire necessity for creation of a Bench at Madurai. The Jaswant Singh Committee which had gone into the subject of creating High Court benches in different parts of the country has also strongly recommended a High Court Bench for Madurai. The State Government of Tamil Nadu from the year 1968 have continuously been persuading the High Court of Madras, the Supreme Court and the Government of India to concede this genuine and propular demand.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): Please conclude.

SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN: I am concluding, Sir. Again on 20th April 1984, the Southern Districts Lawyers' conference held at Madurai passed a unanimous resolution pressing for establishment of a High Court Bench at Madurai. We have a strong case on this subject. We request the Central Government to avoid further delay. I know Mr. Dinesh Goswami, the hon. Law Minister since a lot. I know his ability; I know his will power; I know his straight-forwardness. So I request the hon. Minister and this Government to assure us that the Madurai Bench will be established...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): He has not taken note of your compliments.

SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN: ...as early as possible, without any further delay. Sir, Madurai is the seat of Tamil culture. It is a very good city. All infrastructures have been created. Court buildings have been constructed. The High Court Bench can be housed in that new building. So I request the hon. Minister and the Central Government to have a Bench at Madurai and fulfil our long-standing demand. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): Shri Jogi Three minutes.

SHRI AJIT P.K. JOGI (Madhya Pradesh): You gave four minutes to them

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): You are reducing one minute to every speaker.

SHRI AJIT P.K. JOGI: Mr. Vice-Chairman, Sir, Madhya Pradesh is the largest State of the country. It has an area of 4,43,446 sq. kilometres and in 1981 its population was more than five crores. In 1956, when the States

[Shri Ajit

Reorganisation Commission recommended the formation of Madhya Pradesh, five distinct regions were brought together and one huge State was formed. And that is why, right from the beginning, right from 1956 onwards, the question of providing Benches to all these distinct regions of Madhya Pradesh has been seriously considered. Unfortunately, the Fourth Report of the Law Commission submitted in 1956, the Fourteenth Report of the Law Commission and also in 1972 the High Court Arrears Committee did not think it proper that any additional Bench, should be given to Madhya Pradesh. But there have been persistent demands from the Legislature, from the people's representatives and from the Bars of various regions that additional Benches must be provided to all the distinct regions. My esteemed colleague Mr. Suresh Pachouri has spoken at length for providing a Bench at Bhopal. That is why while supporting the creation of a Bench at Bhopal, I would like to mention and emphasise the case of Raipur which would cover the entire Chhattisgarh region of Madhya Pradesh. Chhattisgarh region which comprises seven districts in three divisions has an area of 1,35,194 sq. kilometres which, I would like to mention, is bigger than 11 States of the country. It has a population of 1,40,00,000 and more, according to the 1981 Census which is bigger than six States of the country. That means Chhattisgarh, area-wise, is bigger than 11 States of the country and population-wise it is bigger than six States of the country and this area is so far away from the seat of the High Court, Jabalpur, that one of the districts, Bastar, is more than 700 kilometres away from Jabalpur. Looking to these factors, creation of a Bench in Chhattisgarh was considered proper by the Jaswant Singh Commission. They mentioned that the Raipur Bench or the Bench at Chhattisgarh would cover seven districts, an area of 1,35,000 sq. kilometres, which is about 30 per cent area of the State and a population of 1.40.00.000 according to the 1981 Census which is about 28 per cent of the population of the State. I would conclude by reading what the Jaswant Singh Commission itself said about the creation of a Bench. It said:

"For the foregoing reasons, we are of the opinion that establishment of a Bench of the High Court for Chhattisgarh region at Raipur will tend to the convenience of a large majority of the people of the region including those of Bastar region which is economically and educationally backward. And the demand for setting up a Bench of Madhya Pradesh High Court is a genuine and a long-standing one of the litigant public of the Chhattisgarh area and the pendency of cases at the principal seat of High Court at Jabalpur is mounting up year after year and mere increase of the judge strength would not solve the problem of the economically and educationally backward sections of the populace in Chhattisgarh region."

....and the cases going to the High Court from this region constitute a sizeable part of the institution at the High Court from the entire area under the jurisdiction of that principal seat at Jabalpur, the only solution which we can suggest is the establishment of a permanent Bench of the High Court at Raipur."

In the last Chapter of the Report, that is, Chapter 9, they have recommended specifically:

"Establishment of a permanent Bench of the M.P. High Court at Raipur with not less than four judges to cater to the needs of the litigant public of Chhattisgarh."

They have also recommended:

"As the establishment of a permanent Bench of the High Court is likely to take some time because of

the procedures to be followed for that purpose, the Chief Justice may take action under section 51(3) of the State Reorganization Act, asking four of his companion Judges to sit at Raipur to exercise jurisdiction in respect of cases arising in the afore-mentioned seven districts."

Sir, I would try to be brief. I would like to plead that Jaswant Singh Commission had examined the entire issue in its totality. They had visited all the places; they consulted the concerned people; they took evidence; they consulted the Supreme Court Judges and the High Court Judges; and they consulted the Bar. Then they came to the conclusion that a Bench must be established in Chhattisgarh. This is a very genuine case. It relates to the most backward and tribal areas of the State. It has a very large population and it has a large area. Therefore, a Bench must be established at Raipur. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI: Now, Mr. Narayanasamy. Please be brief.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I will be very brief.

Sir, I am thankful to Virendra Vermaji who has raised this very important issue, that is, the demand from the various States for setting up of High Court Benches in various places.

Sir, the States have demanded that there should be Benches of the High Courts in the district headquarters or in some important places of their respective States. But the Central Government has to see this issue in a broad-based manner and consider the demands of the various States. One of the criteria to be followed by the Central Government is the pendency of cases which have not been disposed of The other criterion is the proximity of the High Court to the people of the State. And, Sir, the third criterion is the economic condition and the backwardness of the area in which the people are living. These are the three criteria on the basis of which the Centre has to consider the demand. At the moment, the State Governments are approaching the Central Government. Commissions are appointed and these Commissions give their findings and the Central Government keeps the reports of these Commissions safely without implementing them. This is the state of affairs prevailing in our country. Assurances have been given on the floor of the House and also to the people. But they have not been implemented at all.

These demands have been raised by various Members here. Mr. Kiruttinan has mentioned about the setting up of a Bench of the Madras High Court in Madurai in Tamil Nadu. This demand has been there for more than fifteen years. A large number of cases are pending in the Madras High Court. As per the 1989 records, 3,25,636 cases are pending in the Madras High Court. Writ petitions filed in 1980 have not seen the light of day till today. First appeals, second appeals, criminal appeals—all are pending there. But the clients do not know what will be the fate of their cases. I was told that some of the posts of Judges in the Madras High Court have not been filled, about four or five vacancies have not been filled and this is still pending.

Now, the demand made by Shri Kiruttinan is for the setting up of a Bench at Madurai in Tamil Nadu. This is essential and this has been demanded by the people of the State. A Bench of the Madras High Court at Madurai can

Sh. V. Narayana Swamy]

cater to the needs of the southern part of the State.

As fa Pondicherry is concerned, which resent, I would like to say one thing. Delhi is a Union Territory and there is a High Court. Goa had its Judicial Commissioner's Court though it is not there now. It has been abolished and Goa is attached to Maharashtra. But we in Pondicherry have been demanding a Judicial Commissioner's Court there. Our Government has sent its recommendation and it is pending with the Central Government. I would like to know from the honourable Minister whether he agrees to the proposal to set up a Judicial Commissioner's Court in Pondicherry. A large number of cases are pending and for the convenience of the litigant public, I want a Judicial Commissioner's Court to be set up in Pondicherry. Thank you. Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): Now, Dr. Ratnakar Pandey. Please be brief because there are many speakers. This is the Council of States and so, I am trying to give chance to every State.

डा० रत्नाकर पाण्डेय: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं कृतज्ञ हूं आपका कि मुझे आपने श्री वीरेन्द्र वर्मा जी ने जो हाई कोर्ट के बैंचेज़ बढ़ाने के लिए प्रश्न किया था 17 मई, 1990 को उस पर आधे घंटे की चर्चा में बोलने के लिए मौका दिया। वास्तव में अधिकार, कर्तव्य के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्याय, चार जनतंत्र के मूल पाए हैं जिस पर हमारा देश और सारे जनतांत्रिक देशों का ढांचा खड़ा है। न्याय हर व्यक्ति को मिले, स्वतंत्र हो कर अनुशासित ढंग से अपनी बात हर आदमी कह सके, कर्तव्य के प्रति सचेत रहे और अपने अधिकारों का बोध उसे हो।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): आपने केवल एक मिनट मांगा था।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: दो-तीन मिनट। हाई कोर्ट की बैंच इलाहाबाद में है और जैसा कि वर्मा जी ने कहा कि पं० जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा जी, हमारे नेता राजीव गांधी, सब ने वचन दिया था, मैं सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे नेता राजीव गांधी इस पक्ष में थे कि मेरठ और आस-पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के आग्रह पर यह हाई कोर्ट की बैंच मेरठ में खुले, लेकिन वर्तमान प्रधान मंत्री जो प्रयाग के हैं और जब प्रयाग से चुनाव लड़े तो अपने ऐश महल जिसमें माननीय प्रधान मंत्री जी का जो निजी निवास स्थान है वर्तमान प्रधान मंत्री जी का इलाहाबाद में, वहां यह मामला उठा और सारे हाई कोर्ट के वकीलों ने बैठक की कि अगर आपने यह मांग केन्द्र सरकार से स्वीकार कराई, मैं सत्य कह रहा हूं .....**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): कहिए, मगर संक्षेप में कहिए।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: संक्षेप में कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर इलाहाबाद की हाई कोर्ट कहीं दूसरी जगह इसकी बैंच स्थापित हुई तो हम आपको वोट नहीं देंगे और उसी के दबाव में..... **(व्यवधान)**

श्री वीरेन्द्र वर्मा: एडवोकेट्स ने।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: एडवोकेट्स की मीटिंग हुई इलाहबाद के बाय इलेक्शन में ऐश महल में, मैं वर्मा जी, वहां पार्टी के लेवल पर नहीं सोच रहा हूं, सच्चाई कह रहा हूं और आज तक कांग्रेस के शासन में जो कोर्ट नई मेरठ में खुली हाई कोर्ट की बैंच, उसके मूल में माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का दबाव रहा है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और लखनऊ में हाई कोर्ट की बैंचेज़ हैं, सारी कमिशनरियां जितनी हैं उसके विस्तार को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुए समस्त कमिशनरीज़ में एक-एक हाई कोर्ट की बैंच खोला जाना चाहिए। इसके साथ ही, मैं पूर्वांचल से बिलोंग करता हूं। जिसमें गोरखपुर, वाराणसी और फैजाबाद कमिशनरीज आती हैं जिस में 14 जिले आते हैं। नेपाल के बार्डर से लेकर बिहार तक के लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए इलाहाबाद आना पड़ता है। गरीब आदमी को भूखे रहकर, वकीलों की फीस देकर, कोर्ट की सारी औपचारिकताएं कर सात सौ मील दूर से लोग आते हैं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से माननीय न्याय मंत्री और

वर्तमान सरकार के प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से मांग है कि गोरखपुर में, पूर्वांचल में हाई कोर्ट की बैंच मेरठ के साथ ही जरूर खोलनी चाहिए और यह कार्य समानता के भाव से होनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): अब हो गयी बात आपकी।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: फतेहपुर में आए दिन जो गरीबों पर आक्रमण हो रहा है, पिछड़ी जातियों और महिलाओं पर आक्रमण हो रहा है, उस के लिए एक अलग न्यायालय की स्थापना की जाए ताकि प्रधान मंत्री के क्षेत्र के लोगों को न्याय मिल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं कि गोरखपुर में हाई कोर्ट की बैंच अवश्य खोली जाए और प्रत्येक कमिशनरी में यह बैंच खोली जानी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): श्री संघ प्रिय गौतम। बहुत संक्षेप में बोलिए।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बैंच की स्थापना के लिए 1953 से संघर्ष चल रहा है। हर नेता ने, हर राजनीतिक दल ने इस बात को कहा, चौधरी चरणसिंह प्रधान मंत्री रहे, उन्होंने भी कहा, राजीव गांधी प्रधान मंत्री रहे, उन्होंने भी कहा, वह जब सत्ता से हटे, जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट उससे पहले ही आ गयी, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया और कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने कि अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह नहीं लिखा। यहां तक कि वकीलों ने 1981 से सत्याग्रह किया, वकील जेल गए और यहां तक कि आज भी हर हफ्ते के शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए .....**(व्यवधान)**..... वकीलों की हड़ताल रहती है। जसवंत सिंह कमीशन ने भी कहा कि हाई कोर्ट की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि फिर क्या हिचक है।.....**(व्यवधान)**..... सभी कहते हैं कि वादकारी का हित सर्वोच्च है। Litigant's interest is supreme.

हाई कोर्ट ने भी अपनी implied consent से इसे स्वीकार किया है और हर .....**(व्यवधान)**..... जिला कचहरी के कमरे व कार्यालय में यह बैनर लगा हुआ है कि वादकारी का हित सर्वोच्च है.....**(समय की घंटी)** श्रीमन्, दूसरों को आपने पांच-पांच मिनट दिए हैं, मुझे तो दो मिनिट चाहिए।.....**(व्यवधान)**..... वादकारी का हित सर्वोच्च है। इसका मतलब है कि वादी को सस्ता न्याय मिले और शीघ्र न्याय मिले। हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने के पीछे यही भावना है कि वादकारी को सस्ता और शीघ्र न्याय मिले। डा० रत्नाकर पाण्डेय जी ने भी.....

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): उनकी बात का जवाब मत दीजिए, आप अपनी बात कीजिए।

श्री संघ प्रिय गौतम: इसके पीछे एक तो यह तर्क आया कि अगर हाई कोर्ट की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में **(समय की घंटी)** बेंच कायम हो जाती है तो हाई कोर्ट की कुर्सी की गरिमा कम हो जाएगी और दूसरा तर्क यह आया कि वाद बढ़ जाएंगे और तीसरा तर्क यह आया कि **लॉयर्स** का इंटरेस्ट है। महोदय अगर पश्चिम में कोई इंटरेस्ट है तो पूरब में भी **लॉयर्स** का इंटरेस्ट है। महोदय, यदि इन तीनों आशंकाओं को एक तरफ रखा जाए और वादकारी के हित को एक तरफ रखा जाए तो हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना अत्यावश्यक है। मध्य प्रदेश के बारे में कहा गया कि वहां 9 जजों की जगह खाली है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि बहुत केसेज पेंडिंग हैं और जजेज की पूर्ति होनी चाहिए। वहां की सरकार ने, वहां की हाई कोर्ट ने अपनी सिफारिश भेजी.....**(समय की घंटी)**..... मगर न्याय मंत्री उस फाइल को रखे बैठे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया जजों की नियुक्ति शीघ्र करा लें।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): गौत जी, अब समाप्त कीजिए।

श्री संघ प्रिय गौतम: महोदय, अब आखिरी बात कहना चाहता हूं— India is a developing country and ours is a welfare State. इसलिए जजों की जो नियुक्ति हो वह बैकवर्ड एरियाज से आएं और बैकवर्ड कम्युनिटी से आएं। .....**(समय की घंटी)**..... धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): श्री भंवर लाल पंवार। मेहरबानी कर दो मिनिट में खत्म कीजिए।

श्री भंवर लाल पवार (राजस्थान): महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मैं तो संक्षेप में पॉइंटवाइज बोलूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): आप तो बहुत बड़े वकील हैं, पाइंटवाइज कह सकते हैं।

श्री भंवर लाल पंवार: महोदय, मैं गोस्वामी जी का कार्य क्रम करने की बात कर रहा हूं। मैं अपने पूर्व वक्ताओं से भिन्न राय व्यक्त कर रहा हूं।

मान्यवर, हाई कोर्ट में जब मुकदमे जाते हैं तो उस में न तो गरीब को वहां दावा लिखाने के लिए उपस्थित रहने की जरूरत होती है और न गवाहों को वहां लाने की जरूरत होती है, केवल हाई कोर्ट में बहस होती है। अपील के लिए एक जजमेंट की नकल वहां भेजने के बाद वकील बहस कर सकता है। सरल और सस्ते न्याय वाली बात को हमको इस तरह से भी देखना चाहिए कि जहां एकीकृत हाईकोर्ट है, वहां पर स्पेशलाइजेशन होता है, मुकदमों का निर्णय अधिक होता है। हाईकोर्ट में काम करने की प्रणाली पर मैं अपने माननीय साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि सिंगल बेंच बनती है, डिवीजन बेंच बनती है, फुल बेंच बनती है, ला र्जर बेंच बनती है। जहां अलग-अलग खंडपीठ हो गई हैं, वहां ऐसी डिवीजन बेंच और ला र्जर बेंच बनने पर जज भी नहीं मिलते हैं और इस कारण भी मुकदमें काफी संख्या में पेंडिंग रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान में वर्ष 1956 तक एक खंडपीठ जयपुर में थी और एक जोधपुर में थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कांफ्लिक्ट ऑफ जजमेंट न हो। न्याय एक हो, जयपुर से खण्डपीठ हटाकर जो एकीकृत कोर्ट जोधपुर थी, वहां हाईकोर्ट की गई। मान्यवर, यह यूनियन आफ स्टेटस है। भारत की एकता और अखण्डता बनाए रखने के लिए देश का काम चलाने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका होती है। अगर इनको आपने खंडित कर दिया तो स्टेटस का काम अच्छी तरह से नहीं चलेगा। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि इस काम में ज्यादा सफलता तभी मिल सकती है, जब एक ही तरह के मुकदमें एक ही साथ लगने से उनमें एक साथ निर्णय हो सकते हैं। अलग-अलग बेंचों में रहने से ज्यादा खर्चा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा भी ज्यादा होता है और उसमें देरी भी होती है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): अब आप समाप्त कीजिए।

श्री भंवर लाल पंवार: मान्यवर, जहां तक दूरी का सवाल है, अब साइंस और टेक्नोलोजी इतनी डवलप हो गई है कि कहीं दूरी नहीं रहती। मैं आपके माध्यम से माननीय विधि-मंत्री से एक बात और कहना चाहूंगा कि राजस्थान में इस वक्त 11 जजों की पोस्ट खाली हैं और 2 अगले महीने खाली होने जा रही हैं यानी 22 जजों में 13 जज कोर्टों में नहीं। जहां तक जजों की एपायंटमेंट का सवाल है, केन्द्र सरकार के, जो कि पहले की गवर्नमेंट थी, उसके द्वारा मंगाए गए नाम पड़े थे और गवर्नमेंट के चेंज होते ही वे नाम वापस चले गए और नए नाम मंगाए। तो क्या यह सरकार पार्टीजन जजों को मुकर्रर करने जा रही है? अगर यह प्रक्रिया रखी गई तो उस तरह से न्याय बिल्कुल निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो पहले जजों के लिए नाम आए हुए हैं, वे तो रहने चाहिएं और अगर आप और मंगाना चाहें तो उन्हें भी मंगाइए और मंगाकर उन सब का अध्ययन करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पहली सरकार द्वारा मंगाए गए नाम हैं, उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान न दिया जाए और नए नामों को मंगाकर विचार हो। चेन्ज आफ गवर्नमेंट के कारण ऐसा काम नहीं होगा, ऐसा माननीय मंत्री जी सदन को आश्वासन दें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा: और जजेज या एडवोकेट की सुविधा के लिए ही बैंच कायम की जाएं।...**(व्यवधान)**....

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): श्री एस.एस. अहलुवालिया। कृपया तीन मिनिट में समाप्त कर दें।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वीरेन्द्र वर्मा जी का धन्यवादी हूं कि उन्होंने एक अहम मुद्दा माननीय सदन में शॉर्ट-ड्यूरेशन के रूप में लाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम राजा विक्रमादित्य के देश के वासी हैं, जिसने न्याय का एक अच्छा तरीका कायम किया था। एक कहावत है—"जस्टिस डिलेएड इज जस्टिस डिनाइड"। बड़ा आश्चर्य होता है जब हम अपने राज्यसभा और लोकसभा के सवालों के जवाब देखते हैं कि सुप्रीम-कोर्ट में 2,03,158 केसेज पेंडिंग हैं और 6,480 केसेज तो दस साल से भी ज्यादा अवधि से पेंडिंग हैं, जिनकी रेगुलर हियरिंग ही नहीं हो रही है। चूंकि इलाहाबाद की यहां बात हुई, वहां भी उसी तरह से 4,45,039 केसेज पेंडिंग हैं और करीब 30,868 केसेज दस साल से भी ज्यादा अवधि के पेंडिंग हैं।

महोदय, जो लोग देहात से अपना केस हार जाते हैं और जिनके पास पैसा रहता है, वे आगे-आगे बढ़ते जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाईकोर्ट, हाईकोर्ट से सुप्रिम-कोर्ट। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि एक गरीब आदमी के लिए जस्टिस पाना मुश्किल हो गया है क्योंकि जस्टिस पाने के लिए जो मूल चीज है, वह है आज रुपया। अगर उसके पास रुपया नहीं है तो वह अपना केस नहीं लड़ सकता है, जिससे केस लटकता रहता है और अल्टीमेटली वह केस एक्स-पार्टी हो जाता है और उसके हक में जाता है, जो पैसे वाला है, जमींदार है, लैंडलोर्ड है, जो मिल का मालिक है। उसके हक में जाता है, गरीब को न्याय नहीं मिल सकता। गरीब को न्याय दिलाने के लिए अगर सरकार की नीयत सही हो ...**(समय की घंटी)**... साहब, अभी तो 3 मिनट नहीं हुए, आप पहले ही घंटी बजा रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): 3 मिनट हो गए हैं, आप एक मिनट और ले लीजिए।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: गरीब को न्याय दिलाने के लिए अगर सरकार की नीयत सही हो तो इस तरह के हाई कोर्ट खोलने की, सारे हिन्दुस्तान में ज्यादा से ज्यादा खोलने की जरूरत है। मैं अपने आपको सीमित रखना चाहता हूं बिहार में।

बिहार में हम देखते हैं कि पटना हाई कोर्ट और रांची में एक बेंच बैठती है, उसके सिवाय और कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। पूर्णिया से दूर लोग जाते हैं पटना, जितना खर्चा नहीं है, कचहरी में वकील की जितनी फीस नहीं लगती, उससे ज्यादा उसका रहने का खर्चा आता है और उसके लिए केस लड़ना संभव नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से पूर्णिया और दरभंगा में दो हाई कोर्ट बैंचिज़ की मांग करता हूं। साथ ही साथ महोदय, मैं एक और डिमांड करूंगा कि एट्रोसिटीज़ ऑन वीकर सैक्शन जो है, उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए हर एक जगह एक स्पैशल कोर्ट बैठाने की जरूरत है, एक स्पैशल ला देने की जरूरत है क्योंकि उनकी जमीन छीनी जा रही है और सरकार की तरफ से उनको पट्टा मिलता है, उसको जमीन नहीं मिलती है, पोजिशन नहीं मिलती है, उसको यह दिलाने के लिए भी कोई कोर्ट में प्रावधान होना चाहिए और गरीबों की मदद करने के लिए जो सुविधाएं अभी उपलब्ध हैं सरकार की तरफ से, कानूनी तौर पर, वे कम हैं।

सुप्रीम कोर्ट में जब कोई भी गरीब आदमी आता है, चाहे जहां से आए, अगर वह अपना केस अपनी क्षेत्रीय भाषा में ब्रीफ करता है तो उसकी ब्रीफ सुप्रीम कोर्ट में अलाऊ नहीं की जाती है, उससे अंग्रेजी की प्रतिलिपि मांगी जाती है। कृपा करके, अभी कानून मंत्री जी उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा कि इस पर भी ध्यान दें की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, जिस भाषा में भी आपकी जो भी रिकग्राइज़ लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में जो अपनी ब्रीफ देता है, उस ब्रीफ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): श्री मोहम्मद सलीम। 07:00 बजे यह डिस्कशन क्लोज़ करके हम लोग मंत्री महोदय का जवाब सुन लेंगे।

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल): उपसभाध्यक्ष महोदय, काफी देर से यह डिस्कशन चल रही है। आप अगर पश्चिम बंगाल के मैप की तरफ देखेंगे तो यह उत्तर से दक्षिण तक देखने को मिलेगा और कलकत्ता जो है, दक्षिण कोने में है। उत्तरी बंगाल के 5 जिलों में सिलीगुड़ी को सेंटर करके कलकत्ता हाई कोर्ट की एक न्यायपीठ की स्थापना की मांग काफी दिनों से है और जिसके बारे में अक्सर लोग वहां तहरीक भी चला रहे हैं। हमारे यहां यह समस्या नहीं है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के हमारे कुछ दोस्तों ने कहा है कि पूर्व या पश्चिम के मामले पर, कलकत्ता हाई कोर्ट के जो एडवोकेट्स है, उनके अंदर ऐसा विवाद नहीं है, हालांकि प्रोफेशनल इंटरेस्ट होता ही है जो कि एक बाधा है। तो इसलिए मैं यह चाहूंगा कि यह जो न्यायपीठ की स्थापना के बारे में बात हो रही है, काफी बातें आई, तो पश्चिम बंगाल में 5 जिलों के लिए नार्थ बंगाल की सिलीगुड़ी में एक बैंच होनी चाहिए।

इसी तरह से मैं यह कहूंगा कि हाई कोर्ट में, चाहे वह बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, जो वैकेंट पोस्ट हैं जजिज़ की, उनको पूरा करना चाहिए क्योंकि एक अहम मुद्दा यह भी है, तो इनकी जो वेकेन्सिज़ हैं, इसको पूरा करना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI

BHUVNESH CHATURVEDI): Dr. J.K. Jain. Not here. Shri Gopalsinh Solanki.

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to submit to the Government, through your honour, that the High Courts which have been working since long, were introduced after Independence. But the Benches have not been increased since then. The litigation has grown ten to twelve times throughout the nation. The pendency has also grown in the High Courts like hedges and there is no disposal of cases.

So far as Gujarat is concerned, I would like to submit that Panchmal, Baroda, Kheda, Sanbarkanta, Baroch and Surat are backward areas where adivasis are living. Rajkot is also at a distance of 300 kilometres. In between these, there is only one High Court at Ahmedabad. I would like to submit that two Benches, one at Baroda and another at Rajkot, may be introduced so that the litigants are very much facilitated. Not only that. They will have quicker justice. At present, there is delay of justice in Gujarat also like in any State of India. Many cases are pending. That delay is nothing but denial of justice. So, these two Benches may be created. Thank you.

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka) : Sir, when all the States and all my colleagues are demanding Benches, I also thought that I should also demand. Sir, if we are working in the background of taking justice to the doors of the litigants and reduce the pendency in the High Courts and the Supreme Court, we have to find a way out to take the Benches to the doors of the litigants and to increase the number of Benches. I respectfully disagree with Mr. Panwar and...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI) : The whole House disagrees with him.

SHRI, H. HANUMANTHAPPA : Sir, one important aspect is that in 1956 the States have been re-organised But in my State, we had only 9 districts and we had a High Court. Then ten districts have been added with a distance of 600 or 700 miles, and the Benches have not been established. Sir, there is a long-pending demand for establishing a Bench in Dharwar in the northern part of the State. It was earlier in the Bombay Presidency. Sir, districts of four States have joined our State—four districts of Bombay, four districts of Hyderabad, Mangalore and the independent State of Mercara and then Bellary. All these States have sent their districts to include in Karnataka, but no Benches have been bifurcated or established. So, Dinesh Goswamiji knows it very well, and there are reports of the Commission. I know his constraints also. But if the mind of the Government is to take justice to the doors of the litigants, and if you are working in that background, since justice delayed is justice denied, I request the hon. Minister to consider the demand for establishing a Bench in Dharwar, bifurcating the Bangalore High Court.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI) : Hon. Minister.

SHRI VIRENDRA VERMA : Every Member of the House requests for setting up new Benches for the facility of the litigant public.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI) : The Minister will take note of it.

SHRI VIRENDRA VERMA : It is a unanimous demand of the House.

(Interruptions)

THE MINISTER OF STEEL AND MINES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI DINESH GOSWAMI): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am grateful to Mr. Verma for raising this issue and for the views that have been expressed by different Members. All the Members have asked for Benches, and one dissenting voice has come from Mr. Panwar.

SHRI VIRENDRA VERMA: An advocate.

SHRI DINESH GOSWAMI: In this debate itself or in this discussion, Benches have been demanded for Meerut, Agra and Gorakhpur and pandeyji has demanded one Bench in each Commissionerate in Uttar Pradesh — a Bench for Madurai so far as Madras High Court is concerned, and for Bhopal and Raipur in Madhya Pradesh, a Judicial Commissioner's Court in Pondicherry, for Purnea and Darbhanga in Bihar for Siliguri in West Bengal, for Rajkot and Baroda in Gujarat, and for Dharwar in Karnataka. So, before coming to the Benches, I would like to first deal with one point which has been raised regarding the filling up of the vacancies in the High Courts. Nobody is more concerned than me for filling up these vacancies. In fact, immediately after taking office, I took necessary steps to fill up the vacancies. The problem that I faced was that the practice that we have followed so far, not by this Government, but by the earlier Governments, was that whenever there is a change of a constitutional functionary whether it is a chief Minister representing the State or the Governor or the Chief Justice of the High Court, their comments on the recommendations are asked for, and I feel that it is a healthy practice. In fact, I took the highest legal opinion whether it would be proper for me to act on the recommendations which are before me in spite of the fact that there is a change of a constitutional functionary or changes of constitutional functionaries of more than one state.

I have been advised that it would be better to follow the practice that has been followed so far. Now, in Many States, elections took place. Therefore, we had asked for fresh recommendations. But I can assure hon. Members that it was not done with any political motivation. It was done to fulfil the constitutional obligation. I would also assure hon. Member that in the matter of appointment of judges, we are giving the highest priority to the recommendations of the Chief Justices of High Courts and of the Chief Justice of India. I had publicly announced and I am prepared to announce even today— that I would not recommend for appointment as a High Court judge any person unless the Chief Justice concurred with the recommendation.

In spite of the fact that there were so many changes in Government, so many changes of Governors, or, even of Chief Justices, during these six months, I personally feel that I have done a good job. I enquired as to the largest number of appointments that had taken place in a year. I was told that the figure was around 50, or slightly on the higher side. But I would like to point out that in these six months— in fact, not even six months have gone by— we could fill three vacancies in the Supreme Court. There were five acting Chief Justices in different High Courts. we could appoint four permanent Chief Justices in four High Courts. Uptill now, 71 appointments are in the advanced stages of processing. In spite of the fact that in a year, appointments were not more than 50, within six months, we have processed 71 appointments. I think, within a short time, we would be able to fill 78 vacancies.

More than this, in order to remove the complaints of aberrations in the appointment of Judges, or, complaints of political influence, I have introduced a Bill in the Lok Sabha for constitution of a National Judicial Commission for appointment and transfer of judges. The Commission will finally appoint and transfer judges in the sense that the Government is normally bound to accept the Commission's recommendations. If the government does not accept, it shall have to give reasons as to why the recommendations are not accepted. But the government will have no power, in terms of the Bill, to appoint a judge unless the name is recommended by the Commission itself. I think, because of the paucity of time, we may not be able to pass it in

this Session. I hope, when this Bill comes up before the other House and in this House, I will have the support of all sections of the House.

Coming now to the question of constitution of benches, Mr. Panwar expressed his opposition to the constitution of benches. This has been the view of the Law Commission, the High court Arrears Committee and even of the Chief Justices. Reference has been made to the Law Commission's Fourth and Fourteenth Reports in 1956 and 1958 and, the High Court Arrears Committee in 1972 and the Chief Justices' Conferences of 1979 and 1985; they have not really encouraged the creation of benches. But knowing fully well that, today a large number of cases are pending in the different High Courts, and conscious of the fact that justice should reach the doorsteps of the common man, the government is prepared to constitute benches. I can take this House into confidence that after I assumed office, we have been able to constitute a bench; of course, in my own region, in Kohima. Within a very short time, we are going to constitute another bench at Aizawal, Mizoram. But in all these cases, where demands have been made by hon. Members, the problem is not with the Central Government.

The problem is that the other two constitutional functionaries which are to be consulted have not yet given definitive views in these cases. Let us, for example, come to U.P. It has been so forcefully pleaded for a bench for Meerut by Mr. Verma. The Jaswant Singh Committee recommendation was that it should be at Agra. After the Jaswant Singh Committee report was received by the then Government, it was forwarded for comments to different State Governments. Coming to U.P., this is the position. In spite of that we have asked for very definitive views from the State Government. Definitive views are not coming. I have even, after taking over, written letters because there has been pressure, both through Parliament questions and through this discussion today. Different groups and delegations have also met me, one pleading for the bench to be constituted at Meerut and the other at Agra.

SHRI VIRENDRA VERMA: I favour both.

SHRI DINESH GOSWAMI: I have written to the chief Minister stating that we want a definite view from you, where you want the benches to be constituted, but the definite views have not come, may be, because of various reasons. I am conscious of the fact that the Allahabad High Court is opposed to the constitution of the benches. Even then, the moment I got the definite views from the Chief Minister, I can take my own decision in the matter. I have written letters to the Chief Minister in January 1990, February 1990 and March 1990. The hon. Chief Minister has written back to me that the matter is very important and serious and the possibility of emotional reaction persists. He has further expressed that the question, whether the State Government should form its opinion at this stage or should give an opportunity to seek solution for negotiations with the representatives of different sections of the people should be considered in the context of other problems engaging the attention of the people in the State and the country. Therefore, when he has himself referred this that the matter is both serious and emotional, he has also referred that the Government is considering whether the Government should give its views at this stage or should give an opportunity of seeking solution after negotiations or whether it should be considered after some time, these issues are engaging the attention of the State Government itself, I do not think that I can take any decision. I would beg of the hon. Members that they exercise their power over the State Government and see that definite views are given to us and I can assure them that the moment definite views are received by us, I will be the first person to take early action on the same.

So far as Madras is concerned, before we constituted a bench at Madurai the High Court should be satisfied that the necessary infrastructural facilities have been created for the bench. After the High Court writes back to us, after inspection, that they have satisfied themselves that there are infrasturctural facilities, we can issue notification for constitution of the bench. We are enquiring from the Chief Minister of Tamil Nadu whether he has been able to satisfy the High Court regarding the infrastructural facilities. I am waiting for that response. When I get the response from the High Court that the infrastructural facilities are available at Madurai, then at our level we can take a decision.

So far as Karnataka is concerned. I have written to the present chief Minister on 27-2-1990. He has informed me that the High Court of Karnataka is of the view that the establishment of a bench will lead to the lowering of standard. The chief Minister has written to me that he has taken up the mater with the High Court and they are awaiting the response of the High Court. The moment the Chief Minister gets response and writes back to me, I can take a decision.

So far as Madhya Pradesh is concerned, earlier the Madhya Pradesh Government proposed the establishment of benches both at Bhopal and Raipur. Now the Jaswant Singh Commission, of course, recommended Raipur. I would like to make a small correction to my hon. friend, Mr. Pachouri, who said that it was only in Madhya Pradesh that there was no seat of the Court in the capital. This is not correct. There are four States— Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh and Orissa —— where either the principal seat of the High Court or the Bench is not in the capital. Again, in this case, my predecessors in office had written a number of letters almost at regular intervals. I can give the dates also —— on 21.9.88, 27.11.88, 12.1.89, 6.3.89, 30.5.89 and 5.9.89 —— and I have also written to the Chief Minister on 18.4.90 asking for his definite response.

So far as West Bengal is concerned, I have written to the Chief Minister and the Chief Justice for their views.

I can assure this House that once these definite views of the State Governments are received, I can take immediate decision. I would like to further assure the hon. Members that beeasue such a very strong demand has been made in this House, I will again refer in writing to the Chief Ministers. I will be writing to the Chief Ministers of those States from which the demand has come in this House today, conveying to the Chief Minister concerned the very strong feelings of the house and urging upon him to send their definite views. I hope the hon. Members will appreciate that if the definite views do not come from the State Government, well, it is not possible for me to take a unilateral decision. In spite of the fact that Chief Justices of almost all the High Courts are against constitution of Benches, yet I can take a decision considering the fact that today the arrears have become one of the biggest problems, the fact that we must take justice, as far as possible, to the doorsteps of the people and the fact that States like Madhya Pradesh and Uttar Pradesh have very wide geographical area, the population is increasing, peaple have become more assertive of their rights, more conscious of their rights and people are going to courts to exercise their own right. Therefore, may be even the Chief Justices decision may require a fresh look and so I would only urge all the hon. Members to please be in touch with their respective State Governments and help us in getting definite views from the State Government so that we can take decisions in the matter Thank you.

SHRI B.L. PANWAR: Will the Minister write to the Chief Minister of Rajasthan for a unified High Court and get his

[Shri B.L.Panwar]

comments becasue I am in favour of a unified High Court?

SHRI DINESH GOSWAMI: Mr. Panwar's view is probably and isolated view here. Now I would not like to open a new arena of discussion. I will only write about the Benches to them and I leave it to him to be in touch both with the Chief Minister and the Chief Justice.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): The House is adjourned till 11 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at thirteen minutes past seven of the clock till elven of the clock on Tuesdy, the 29th May, 1990.